मेन्स मास्टर

जानूस-सामना वाली अर्थव्यवस्था के संक्षिप्त विवरण

प्रसंग

यह लेख भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्विरोधों पर प्रकाश डालता है, जहां उच्च-विकास संकेतक संकट के संकेतों के साथ मौजूद हैं, जिससे दो-मुंह वाले रोमन देवता जानूस जैसी स्थिति पैदा होती है।

पृष्ठभूमि

जैसे-जैसे भारत चुनावों के लिए तैयार हो रहा है, सरकार अपनी आर्थिक सफलताओं पर जोर दे रही है: तेजी से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, महत्वपूर्ण गरीबी में कमी, और एक संपन्न शेयर बाजार। हालाँकि, आलोचक इन दावों की वैधता और समावेशिता पर संदेह जताते हैं।

क्या भारत सचमुच चमक रहा है?

उत्तर सूक्ष्म और बहुआयामी है। जबकि कुछ डेटा बिंदु समृद्धि (कार की बिक्री, हवाई यात्रा और निवेश में वृद्धि) की तस्वीर पेश करते हैं, अन्य एक व्यथित और संघर्षरत पेट को प्रकट करते हैं:

• **57% आबादी:** इसका मतलब है कि 813 मिलियन लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर निर्भर हैं, जो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने वाला एक सरकारी कार्यक्रम है। यह विशाल संख्या आर्थिक सुरक्षा की व्यापक कमी और आर्थिक विकास के संभावित सीमित प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करती है।

• **ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों (मनरेगा) की मांग सर्वकालिक उच्च स्तर पर:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के काम की गारंटी देती है। एमजीएनआरईजीएस नौकरियों की बढ़ती मांग सरकार की बढ़ती अर्थव्यवस्था की कहानी का खंडन करती है और लगातार ग्रामीण बेरोजगारी और अल्परोजगार का सुझाव देती है।

• **पिछले पांच वर्षों में वास्तविक ग्रामीण मजदूरी में नकारात्मक वृद्धि:** यह इंगित करता है कि ग्रामीण क्षेत्र के भीतर भी, मजदूरी मुद्रास्फीति के साथ तालमेल नहीं रख रही है, बढ़ती कीमतों के कारण इसमें काफी कमी आई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और आर्थिक कठिनाई और बढ़ जाती है।

• **ग्रामीण ऋणग्रस्तता का उच्च स्तर:** यह ग्रामीण परिवारों के बीच ऋण के बोझ की व्यापकता को दर्शाता है, जो अक्सर बुनियादी जरूरतों को पूरा करने या कृषि में निवेश करने के लिए ऋण का सहारा लेते हैं। यह कर्ज़ का बोझ आर्थिक विकास को रोकता है और परिवारों को गरीबी के चक्र में फंसा देता है।

"आर्थिक द्वैतवाद" क्या है?

आर्थिक द्वैतवाद का तात्पर्य एक ही देश के भीतर दो या दो से अधिक विशिष्ट आर्थिक प्रणालियों के सह-अस्तित्व से है। भारत के संदर्भ में, यह एक स्थिर, अनौपचारिक और बड़े पैमाने पर कृषि ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ मौजूद एक आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत और बढ़ते शहरी क्षेत्र के रूप में प्रकट होता है। यह असमान विकास आय, अवसरों और जीवन स्तर में भारी असमानता पैदा करता है।

भारत में आर्थिक द्वैतवाद की व्यापकता के संकेत:

• **विकास के दावे के बावजूद मुफ्त भोजन योजनाओं पर उच्च निर्भरता:** यह सरकार की संपन्न अर्थव्यवस्था की कहानी और व्यापक खाद्य असुरक्षा की वास्तविकता के बीच असंगतता को उजागर करता है।

• **उच्च विकास के दावों के साथ-साथ मनरेगा नौकरियों की बढ़ती मांग:** यह विरोधाभास विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका बनाने पर आर्थिक विकास के सीमित प्रभाव को उजागर करता है।

• **तेजी से बढ़ते शेयर बाजार के साथ-साथ नकारात्मक ग्रामीण वेतन वृद्धि:** यह असमानता आर्थिक विकास के लाभों के असमान वितरण को दर्शाती है। जबकि शेयर बाज़ार फल-फूल रहा है, आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका और जीवन स्तर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्थिर या बिगड़ रहे हैं।

आशय:

• **आर्थिक विकास से होने वाले लाभों का असमान वितरण:** आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे आय का अंतर और सामाजिक असमानताएं बढ़ रही हैं।

• **सामाजिक अशांति की संभावना:** आर्थिक अन्याय की भावना के साथ अधूरी बुनियादी जरूरतें, सामाजिक अशांति और अस्थिरता को बढ़ावा दे सकती हैं।

• **2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में चुनौतियाँ:** एसडीजी का लक्ष्य अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाना है। हालाँकि, भारत का आर्थिक द्वंद्ववाद 2030 के लक्ष्य वर्ष तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

• **ऐसी नीतियां जो आधुनिक शहरी क्षेत्र और पारंपरिक ग्रामीण क्षेत्र के बीच अंतर को पाटती हैं:** इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश, ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल और शिक्षा का विकास और कृषि उत्पादकता और विविधीकरण को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।
• **ग्रामीण विकास और आय सृजन पर ध्यान:** इसमें रोजगार के अवसर पैदा करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और ग्रामीण व्यवसायों के लिए ऋण और बाजार तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना शामिल है।
• **शिक्षा और कौशल में निवेश:** यह व्यक्तियों को आधुनिक अर्थव्यवस्था में सार्थक रूप से भाग लेने और उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेगा।
• **समावेशी विकास को बढ़ावा देना:** इसके लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करें कि समाज के सभी वर्गों को आर्थिक विकास से लाभ हो, जिससे भारत के लिए अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ विकास मार्ग प्रशस्त हो सके।

इन महत्वपूर्ण उपायों के माध्यम से आर्थिक द्वैतवाद को संबोधित करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी आर्थिक वृद्धि वास्तव में टिकाऊ हो और उसके सभी नागरिकों को लाभ हो

जीवन और आजीविका

प्रसंग

यह लेख झूठे बहानों के तहत भारतीय प्रवासियों को संघर्ष क्षेत्रों में ले जाने के मुद्दे और भारत सरकार द्वारा बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा करता है।

पृष्ठभूमि

भारत सरकार ने हाल ही में स्वीकार किया कि भारतीय नागरिकों को रूसी सेना द्वारा भर्ती किया गया था और युद्धग्रस्त यूक्रेन में तैनात किया गया था। यह घटना इजराइल जैसे अन्य संघर्ष क्षेत्रों में नौकरियों के लिए भारतीयों की भर्ती की रिपोर्टों के बाद हुई है।

भारत के प्रवासन की समस्या

• **जागरूकता की कमी:** भारतीयों को ऑनलाइन विज्ञापनों और बिचौलियों द्वारा गुमराह किया जाता है जो संघर्ष क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

• **ऋण और वित्तीय दबाव:** महत्वपूर्ण रकम खर्च करने या ऋण लेने के बाद, कुछ भारतीय फंसे हुए महसूस करते हैं और नौकरी की वास्तविक प्रकृति को समझने के बाद भी खतरनाक परिस्थितियों में काम करना जारी रखते हैं।

• **अपर्याप्त सरकारी उपाय:** "उत्प्रवास जांच आवश्यक" सूची सहित वर्तमान प्रणाली, भारतीयों को शोषण से बचाने के लिए अपर्याप्त है।

• **जोखिम भरी भर्ती के लिए सरकार की मंजूरी:** इजराइल जैसे संघर्ष क्षेत्रों में भर्ती अभियान के लिए सरकार की हरी झंडी अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के बारे में चिंता पैदा करती है।

नतीजे

• युद्ध क्षेत्र में काम करते समय भारतीयों को नुकसान और यहां तक कि मौत का भी सामना करना पड़ता है।

• स्थिति के कारण परिवारों को भावनात्मक और वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ता है।

• नागरिकों के शोषण की खबरों से भारत की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।

गंभीर अनुमान

लेख में सरकार की आलोचना की गई है:

• यूक्रेन में भारतीयों के मुद्दे पर विलंबित प्रतिक्रिया।

• समान स्थितियों को रोकने के लिए सक्रिय उपायों का अभाव।

• प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों के लिए अपर्याप्त सहायता।

• मौजूदा जोखिमों के बावजूद अन्य संघर्ष क्षेत्रों में भर्ती को मंजूरी देना।

आगे बढ़ने का रास्ता

• **व्यापक प्रोटोकॉल लागू करें:** इन प्रोटोकॉल में अनुबंधों की कड़ी जांच, बेहतर प्रस्थान-पूर्व मार्गदर्शन और मुसीबत में फंसे प्रवासियों के लिए मजबूत समर्थन संरचनाएं शामिल होनी चाहिए।

• **क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाएँ:** समान मुद्दों का सामना करने वाले पड़ोसी देशों के साथ सहयोग से कमजोर व्यक्तियों को लक्षित करने वाले भर्ती नेटवर्क को खत्म करने में मदद मिल सकती है।

• **आर्थिक संकट का समाधान:** हालाँकि यह कोई त्वरित समाधान नहीं है, लेकिन सरकार को समस्या के मूल कारण - भारत में नौकरी के अवसरों की कमी - का समाधान करने की ज़रूरत है ताकि हताश व्यक्तियों को विदेश में जोखिम भरा काम खोजने से रोका जा सके।

• **सहानुभूति दिखाएं:** सरकार को लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए और उनकी सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इन कदमों को उठाकर, भारत सरकार अपने नागरिकों को शोषण से बेहतर ढंग से बचा सकती है और विदेश में काम मांगने पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।

ताकत बनाम कारण

यह लेख महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठों के लिए 10% आरक्षण देने वाले हाल ही में पारित विधेयक की वैधता और चुनौतियों की जांच करता है।

पृष्ठभूमि:

• विधेयक को संभावित कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अतीत में इसी तरह के प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है।

• यह पिछले एक दशक के भीतर मराठों के लिए आरक्षण सुरक्षित करने का महाराष्ट्र सरकार का तीसरा प्रयास है।

आरक्षण क्यों दिया गया:

• सरकार मराठा समुदाय द्वारा डाले गए भारी राजनीतिक दबाव का हवाला देती है, जो राज्य के भीतर काफी राजनीतिक प्रभाव रखता है।

• अन्य ओबीसी समूहों के प्रत्याशित विरोध के कारण मौजूदा 19% ओबीसी कोटा के भीतर आरक्षण देना अव्यावहारिक माना गया।

न्यायिक जांच की चुनौतियाँ:

• सुप्रीम कोर्ट ने पहले 50% से अधिक आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया था और आरक्षण के लिए पात्र पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए केंद्र सरकार के एकमात्र अधिकार की स्थापना की थी।

• जबकि अदालत ने 2022 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% कोटा को बरकरार रखा, इस फैसले के दीर्घकालिक प्रभाव अनिश्चित बने हुए हैं।

सभी समुदायों में आरक्षण की बढ़ती मांग:

• मराठों का मामला भारत में विभिन्न समुदायों में आरक्षण की बढ़ती मांगों का उदाहरण है।

• ये मांगें अक्सर ऊपर की ओर गतिशीलता और बेहतर सामाजिक-आर्थिक अवसरों की गहरी इच्छा से उत्पन्न होती हैं।

व्यापक आउटलुक:

लेख आरक्षण की मांगों को संबोधित करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता का प्रस्ताव करता है:

• आगामी दशकीय जनगणना के साथ-साथ एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक जनगणना आयोजित करने से देश भर में विभिन्न समुदायों द्वारा अनुभव किए गए पिछड़ेपन की वास्तविक सीमा के संबंध में अधिक विश्वसनीय डेटा प्रदान किया जा सकता है।

• यह डेटा सकारात्मक कार्रवाई की एक नई, साक्ष्य-आधारित प्रणाली विकसित करने की नींव के रूप में काम कर सकता है जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति सच्चा रहते हुए निष्पक्ष और न्यायसंगत है।

इन कदमों को लागू करके, भारत अपनी विविध आबादी के भीतर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए अधिक न्यायसंगत और डेटा-संचालित दृष्टिकोण की ओर बढ़ सकता है।

भारत के बच्चों में निवेश का आर्थिक मामला

यह लेख भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) में निवेश बढ़ाने का तर्क देता है, बावजूद इसके कि इसकी वर्तमान स्थिति कम वित्तपोषित और कम खोजे गए क्षेत्र के रूप में है।

'पृष्ठभूमि:

• अपने जनसांख्यिकीय लाभांश, शैक्षिक फोकस और नौकरियों पर जोर देने के बावजूद, भारत ने दशकों से लगातार ईसीसीई की उपेक्षा की है।

• ईसीसीई को अक्सर महज बच्चों का खेल या घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाता है, जिसे परंपरागत रूप से महिलाओं का काम माना जाता है। यह धारणा इसके कम निवेश और कम मूल्यांकन में योगदान करती है।

बच्चों में निवेश: एक आर्थिक दृष्टिकोण

• मानव पूंजी, किसी आबादी का सामूहिक ज्ञान, कौशल और अनुभव, किसी देश की समृद्धि की नींव मानी जाती है। प्रारंभिक बचपन वह महत्वपूर्ण चरण है जहां यह नींव रखी जाती है। ईसीसीई में निवेश करके, हम भावी पीढ़ियों के संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में निवेश करते हैं, उनकी भविष्य की सफलता के लिए आधारशिला रखते हैं।

• ईसीसीई निवेश में वृद्धि से शैक्षिक प्राप्ति में सुधार हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो बच्चे उच्च गुणवत्ता वाले प्रारंभिक बचपन के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, उनके हाई स्कूल से स्नातक होने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और भविष्य में बेहतर वेतन वाली नौकरियां हासिल करने की अधिक संभावना होती है। इससे अधिक कुशल और उत्पादक कार्यबल तैयार होता है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ होता है।

• ईसीसीई में निवेश से बच्चों के स्वास्थ्य पर बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। ये कार्यक्रम पौष्टिक भोजन, निवारक स्वास्थ्य सेवाओं और विकासात्मक देरी के लिए शीघ्र हस्तक्षेप तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। इससे जनसंख्या स्वस्थ होती है, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर बोझ कम होता है और उनके जीवन भर उत्पादकता में वृद्धि होती है।

• ECCE में निवेश करने से सामाजिक अशांति को कम करने में भी मदद मिल सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो बच्चे बचपन में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके वयस्क होने पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना कम होती है। इससे सुरक्षित समुदाय और अधिक स्थिर समाज का निर्माण हो सकता है।

• **नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स हेकमैन** के एक अध्ययन सहित दुनिया भर के शोध, बचपन में निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर के निवेश पर 13% वार्षिक रिटर्न का सुझाव देते हैं। इससे लंबे समय में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिलते हैं, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में कमी और अधिक उत्पादक कार्यबल से कर राजस्व में वृद्धि शामिल है।

• आंगनवाड़ी प्रणाली, दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक ईसीसीई प्रदाता, भारत में छह वर्ष से कम उम्र के 80 मिलियन से अधिक बच्चों को सेवा प्रदान करती है। अध्ययनों से पता चला है कि जो बच्चे आंगनबाड़ियों में जाते हैं, वे ऐसा न करने वाले बच्चों की तुलना में लगातार बेहतर संज्ञानात्मक और मोटर कौशल प्रदर्शित करते हैं, जो इसके सकारात्मक प्रभाव को उजागर करता है।

वर्तमान खामियाँ और नीतिगत खामियाँ:

• **अपर्याप्त फंडिंग:** बड़ी और अधिक कमजोर आबादी की जरूरतों को पूरा करने के बावजूद, आंगनवाड़ी प्रणाली को उच्च शिक्षा जैसे अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम आवंटन मिलता है। यह वित्तीय बाधा गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने और सभी पात्र बच्चों तक पहुंचने की इसकी क्षमता में बाधा डालती है।

• **भारत में ईसीसीई के व्यापक आर्थिक प्रभावों पर सीमित शोध:** जबकि बेहतर स्वास्थ्य और शैक्षिक प्राप्ति जैसे व्यक्तिगत लाभों का दस्तावेजीकरण किया गया है, इन्हें बड़ी हुई जीडीपी या कम सामाजिक अशांति जैसे मात्रात्मक व्यापक आर्थिक लाभों में अनुवादित करने का व्यापक रूप से पता नहीं लगाया गया है। डेटा की कमी के कारण केवल आर्थिक तर्कों के आधार पर बढ़े हुए निवेश की वकालत करना मुश्किल हो जाता है।

• **सूक्ष्म-स्तरीय लाभों पर ध्यान दें:** मौजूदा अनुसंधान और नीतिगत चर्चाएं अक्सर ईसीसीई के व्यक्तिगत लाभों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जैसे कि बच्चों के लिए बेहतर संज्ञानात्मक विकास। हालाँकि, इन सूक्ष्म-स्तरीय लाभों को व्यापक व्यापक आर्थिक तस्वीर से जोड़ना और उनके दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव को प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण निवेश हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।

आशय:

• अपर्याप्त ईसीसीई नुकसान के चक्र को जन्म दे सकता है। जिन बच्चों के पास गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन के कार्यक्रमों तक पहुंच नहीं है, उन्हें सीखने में कठिनाइयों, खराब स्वास्थ्य और विकास संबंधी देरी का अनुभव होने की अधिक संभावना है। इससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि में बाधा आ सकती है, जिससे कमाई की संभावना कम हो सकती है और वयस्कता में अवसर सीमित हो सकते हैं। यह, बदले में, गरीबी, सामाजिक बहिष्कार और यहां तक कि सामाजिक अशांति में योगदान दे सकता है।

• ईसीसीई में निवेश में देरी से मानव पूंजी विकास के अवसर चूक सकते हैं। एक बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्ष मस्तिष्क के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खिड़की होते हैं। ईसीसीई की उपेक्षा करके, हम भविष्य की पीढ़ियों की पूरी क्षमता में निवेश करने में असफल होने का जोखिम उठाते हैं, जिससे भारत की दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक प्रगति बाधित होती है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

• ईसीसीई के लिए आर्थिक मामले को पूरी तरह से अपनाने के लिए, विभिन्न पहलुओं में बढ़े हुए निवेश की आवश्यकता है, जिसमें शामिल हैं:

◦ **बुनियादी ढांचे में सुधार:** व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करना और नए केंद्रों का निर्माण करना।

◦ **क्षमता निर्माण:** आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और देखभाल करने वालों के लिए व्यापक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल और शिक्षा प्रदान कर सकें।

◦ **गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री:** आयु-उपयुक्त शिक्षा प्रदान करन

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org

प्रमुख कंपनियाँ अभी भी वनों की कटाई से निपटने में विफल हो रही हैं: ग्लोबल कैनोपी

• व्यापक विफलता: ग्लोबल कैनोपी की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि वनों की कटाई से जुड़ी कई प्रमुख कंपनियों ने 10 वर्षों की निगरानी और चेतावनियों के बावजूद वनों की कटाई की नीतियों को लागू नहीं किया है।
• कार्रवाई की तात्कालिकता: रिपोर्ट नियमों की तात्कालिकता पर जोर देती है क्योंकि कंपनियों और वित्तीय संस्थानों की स्वैच्छिक कार्रवाइयां अप्रभावी रही हैं।
• यूरोपीय संघ विधान: रिपोर्ट नए यूरोपीय संघ कानून का स्वागत करती है लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अन्य क्षेत्रों से सख्त कार्यान्वयन और त्वरित कार्रवाई का आग्रह करती है।
• पारदर्शिता पर ध्यान: रिपोर्ट में पारदर्शिता की कमी पर प्रकाश डाला गया है, कई कंपनियां पर्याप्त सबूत प्रदर्शित करने में विफल रही हैं कि उनके कार्य उनकी घोषित प्रतिबद्धताओं से मेल खाते हैं।
• व्यापक फोकस का आह्वान: जबकि पाम तेल वनों की कटाई को संबोधित करने में प्रगति देखी गई है, रिपोर्ट मवेशी उत्पादन जैसे अन्य प्रमुख कारकों पर समान ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देती है।

विवरण:
• रिपोर्ट, "फ़ॉरेस्ट 500", उष्णकटिबंधीय जंगलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली कंपनियों और वित्तीय संस्थानों का विश्लेषण करती है, जो ताड़ के तेल, सोया और लकड़ी जैसी वस्तुओं में उनकी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है।
• विश्लेषण की गई 23% संस्थाओं ने एक दशक की निगरानी के बावजूद वनों की कटाई की एक भी प्रतिबद्धता प्रकाशित नहीं की है।
• ग्लोबल कैनोपी सख्त नियमों का आग्रह करता है क्योंकि स्वैच्छिक कार्यों ने पूर्ण वनों की कटाई-मुक्त आपूर्ति श्रृंखला हासिल नहीं की है।
• वर्तमान में केवल 1% कंपनियाँ वनों की कटाई पर नए यूरोपीय संघ कानून का अनुपालन करने की राह पर हैं।
• जनता के दबाव से कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन 37% संस्थाओं में अभी भी सार्वजनिक वनों की कटाई की प्रतिबद्धता का अभाव है।
• जेपी मॉर्गन चेज़, बैंक ऑफ अमेरिका और मित्सुबिशी यूएफजे जैसे वित्तीय संस्थानों को वनों की कटाई प्रतिबद्धताओं की कमी वाली कंपनियों के शीर्ष फाइनेंसरों के रूप में नामित किया गया है।
• एडिडास, स्टारबक्स और गैप जैसी कंपनियों को उनकी वनों की कटाई की प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त सबूत होने का हवाला दिया गया है।
• रिपोर्ट में ताड़ के तेल से परे व्यापक ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, और वनों की कटाई में मवेशी उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका पर अधिक ध्यान देने का आग्रह किया गया है।
कुल मिलाकर, रिपोर्ट बढ़ती जागरूकता के बावजूद वनों की कटाई के लगातार मुद्दे पर प्रकाश डालती है और कंपनियों और वित्तीय संस्थानों से सख्त नियमों और बेहतर पारदर्शिता की मांग करती है।

प्रीलिम्स बूस्टर

भीषण गर्मी में वियतनाम का 'धान का कटोरा' टूट गया

- हो ची मिन्ह सिटी और मेकांग डेल्टा क्षेत्र सहित दक्षिणी वियतनाम ने फरवरी में असामान्य रूप से लंबे समय तक गर्मी का अनुभव किया, तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो अप्रैल या मई में सामान्य गर्म मौसम के चरम से काफी अधिक था। 🌡️
- मेकांग डेल्टा क्षेत्र भी सूखे से जूझ रहा है, जिससे नहरों में पानी का स्तर कम हो गया है और किसानों के लिए अपनी फसलों के परिवहन में चुनौतियां पैदा हो रही हैं। 💧
- लू और सूखे के प्रभाव के कारण गंभीर सूखापन पैदा हो गया है, जिससे किसानों के लिए परिवहन के लिए जलमार्गों का उपयोग करना मुश्किल हो गया है और क्षेत्र में चावल की खेती पर प्रभाव के बारे में चिंता पैदा हो गई है। 🌾
- दक्षिणी मौसम विज्ञान और जल विज्ञान प्रशासन के मुख्य भविष्यवक्ता ने लंबे समय तक शुष्क रहने के लिए अल नीनो मौसम की घटना और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों को जिम्मेदार ठहराया, और क्षेत्र के मौसम पैटर्न पर इन कारकों के प्रभाव पर जोर दिया। 🌍
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बताया कि 2023 विश्व स्तर पर रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था और एल नीनो जलवायु पैटर्न के कारण 2024 में और भी अधिक तापमान की संभावना की चेतावनी दी, जो आम तौर पर 2023 के मध्य में उभरने के बाद एक वर्ष के लिए वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। 🌎

दुर्लभ बीमारियों के खिलाफ भारत की लड़ाई

- 19 वर्षीय बाल अभिनेत्री सुहानी भटनागर की एक दुर्लभ बीमारी, डर्मेटोमायोसिटिस से दुखद मौत, दुर्लभ रोग दिवस के साथ हुई, जो दुर्लभ चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली उपेक्षा और कलंक को उजागर करती है। 💔
- प्रति 1,000 जनसंख्या पर 1 या उससे कम को प्रभावित करने वाली दुर्लभ बीमारियाँ, भारत में 450 से अधिक चिन्हित बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनमें लगभग 8-10 करोड़ भारतीय प्रभावित हैं, जिनमें मुख्य रूप से बच्चे शामिल हैं। हालाँकि, संसाधन की कमी और सीमित जागरूकता, निदान और दवा विकास के कारण इन बीमारियों की उपेक्षा हुई है। 🏥
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2017 में दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई लेकिन कार्यान्वयन चुनौतियों के कारण 2018 में इसे वापस ले लिया। दुर्लभ बीमारियों के लिए संशोधित राष्ट्रीय नीति (एनपीआरडी) की घोषणा 2021 में की गई थी, लेकिन दुर्लभ बीमारियों के लिए एक मानक परिभाषा की कमी और अपर्याप्त धन सहित समस्याएं बनी हुई हैं। 📉
- दुर्लभ बीमारी के प्रबंधन के लिए समय पर और सटीक निदान महत्वपूर्ण है, फिर भी रोगियों को अक्सर देरी का सामना करना पड़ता है, निदान में औसतन सात साल लग जाते हैं। भारत में पहचानी गई 50% से भी कम दुर्लभ बीमारियों का इलाज संभव है, और केवल 20 दुर्लभ बीमारियों का इलाज सीमित संख्या में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) से उपलब्ध है। ⏳
- अपर्याप्त धन, असमान वितरण और आवंटित धन के कम उपयोग के बारे में चिंताओं के साथ, दुर्लभ बीमारियों के लिए बजट आवंटन कम रहता है। एनपीआरडी दिशानिर्देश प्रति मरीज ₹50 लाख तक की अनुमति देते हैं, जिसे पुरानी दुर्लभ बीमारियों के आजीवन प्रबंधन और उपचार के लिए अपर्याप्त माना जाता है। 💰
- दुर्लभ बीमारियों से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों को मान्यता दी गई है, लेकिन दुर्लभ बीमारियों की एक मानक परिभाषा, बजटीय परिव्यय में वृद्धि, दवा विकास और चिकित्सा के लिए समर्पित धन, और बेहतर समन्वय और जिम्मेदार निधि उपयोग की आवश्यकता है। राज्य सरकारें, सार्वजनिक और निजी कंपनियां और सीएसआर पहल भी इन चुनौतियों से निपटने में भूमिका निभा सकती हैं। 📈
- दुर्लभ बीमारियों के लिए आवश्यक उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए घरेलू निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन, कम नैदानिक परीक्षण आवश्यकताओं और जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को हटाने की आवश्यकता के साथ, अत्यधिक दवा की कीमतों और उपलब्धता को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। 💊

संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों ने अशांत डीआर कांगो से वापसी शुरू कर दी है

- संयुक्त राष्ट्र ने पूर्वी क्षेत्र में जारी हिंसा के बारे में संयुक्त राष्ट्र की चिंताओं के बावजूद वापसी की डीआरसी की मांग के जवाब में, संयुक्त राष्ट्र बेस को राष्ट्रीय पुलिस को सौंपकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) से मोनुस्को शांति सेना की वापसी की शुरुआत की। देश की। 🕊️
- डीआरसी सरकार संयुक्त राष्ट्र बल को सशस्त्र समूहों और मिलिशिया से नागरिकों की रक्षा करने में अप्रभावी मानती है जो तीन दशकों से देश के पूर्वी हिस्से में एक दीर्घकालिक मुद्दा रहा है। 🇨🇩
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मोनुस्को मिशन को धीरे-धीरे हटाने की मंजूरी दे दी, जो 1999 से डीआरसी में मौजूद है, वर्तमान में लगभग 13,500 सैनिक और 2,000 पुलिस इटुरी, दक्षिण किवु और उत्तरी किवु के पूर्वी प्रांतों में तैनात हैं। 🚐
- वापसी की योजना तीन चरणों में तय की गई है, जिसमें बुरुंडी की सीमा से लगे कामन्योला में पहला बेस सौंपा जाएगा, और बाद के चरणों में दक्षिण किवु से सैन्य शांति सैनिकों का प्रस्थान और डीआरसी सुरक्षा बलों को बेस का हस्तांतरण शामिल होगा। 🏞️
- यह वापसी उत्तरी किवु में तुत्सी के नेतृत्व वाले एम23 विद्रोहियों के पुनरुत्थान के बीच हुई है, जिन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जिससे क्षेत्र में जटिल सुरक्षा चुनौतियां बढ़ गई हैं। ⚠️

शीर्ष स्पेनिश अधिकारी पनडुब्बी के लिए सौदा पेश कर सकते हैं

- स्पेन की नवंतिया और जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (टीकेएमएस) छह पी-75आई पनडुब्बियों के लिए भारत की मेगा-सौदे के लिए दो दावेदार हैं, नवंतिया के रक्षा राज्य सचिव, एम्पारो वाल्कारसे, भारतीय रक्षा के साथ पनडुब्बी सौदे पर चर्चा करने के लिए भारत आने वाले हैं। सचिव गिरिधर अरमाने. 🇪🇸🇩🇪
- पनडुब्बी सौदा, जिसकी लागत ₹43,000 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है, को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया के रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत संसाधित किया जा रहा है, जिसमें नवंतिया ने लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) और टीकेएमएस ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) के साथ समझौता किया है। इस सौदे के लिए केवल दो भारतीय कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 💰
- नवंतिया अपनी S80 वर्ग की पनडुब्बियों के आधार पर P-75I पनडुब्बियों को डिजाइन करेगा, जिनके निर्माण के लिए L&T जिम्मेदार है, और स्पेन उच्च दक्षता के साथ अगली पीढ़ी के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) मॉड्यूल सहित पूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रदान करने के लिए तैयार है। . 🚢
- उम्मीद है कि स्पेन की नवंतिया यात्रा के दौरान अपने एआईपी मॉड्यूल को साबित करने में अपनी प्रगति पर जोर देगी, और सरकारी गारंटी प्रदान करेगी क्योंकि यह एक राज्य के स्वामित्व वाला शिपयार्ड है, जो पनडुब्बी सौदे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। 🛠️

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org